मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

नगर निगम का गोरख धंधा, निर्माणों को तोड़ना और बनवाना 3

गरीबी और प्रधानमन्त्री मोदी
स्त्री के सशक्तीकरण का राजनीतिक एजेंडा 4

कामागाटा मारू घटना
व्यवस्था का एक रक्षक भूतनाथ लौटकर आया 6

गडकरी के 'अच्छे दिन' आये उसे चोर बताने वाले जेल गये 8

वर्ष 27 अंक 14 फरीदाबाद, वीरवार, 1-15 जून 2014 फोन : - 9999595632 ₹ 2

भ्रष्टाचारी बना मन्त्री और व्हिसिल ब्लोअर को घेरे संतरी

गडकरी का खेल: कोर्ट मांगे बेल, केजरी को जेल

मानहानि के मुकदमे में बेल बॉंड न भरकर जेल जाने वाले अरविंद केजरीवाल ने देश की न्याय व्यवस्था को एकबारगी कठघरे में खड़ा कर दिया। चाहे न्याय पालिका को 'पवित्र गाय' का दर्जा देने वालों की कमी नहीं है पर केजरीवाल प्रसंग ने न्यायिक प्रक्रिया में देरी, खर्चीलेपन और जन-विमुखता जैसी बुराइयों को रेखांकित करने का जरूरी काम अंजाम दिया है।

मज़दूर मोर्चा, दिल्ली ब्यूरो

अन्ततः 'आप' के संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उच्च न्यायालय की जिद के सामने यू टर्न करना पड़ा। 21 मई से तिहाड़ जेल में बंद अरविंद का मामला 26 मई को सुलटा जब उन्होंने बेल बांड भरने की हां कर दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसे 'छोटा सा मामला' कह कर उनके वकीलों की मार्फत यही सलाह दी थी।

क्या वास्तव में यह छोटा सा मामला है? क्या इससे न्यायपालिका की अपनी साख जुड़ी हुयी नहीं है? भ्रष्टाचार खत्म करने की लड़ाई लड़ने वाले को तो जेल जाना पड़े और भ्रष्टाचारी केन्द्र सरकार में कैबिनेट मंत्री होने की शपथ ले! क्या इसमें कुछ भी ऐसी गंभीर विसंगति नहीं कि देश की स्वतंत्र न्यायपालिका सम्बन्धित प्रक्रियाओं में परिवर्तन लाए?

सवाल यह है कि दूसरों को पाबंद करने वाली अदालतें स्वयं काम निबटाने के प्रति कितनी पाबंद हैं? सभी को पता है कि मानहानि या इस जैसे तमाम मामलें अदालतों में वर्षों चलते रहते हैं। कायदे से तो हर अदालत को समय-समय पर बांड भरना चाहिए कि यदि समय-सीमा में मुकदमों का निबटारा नहीं हुआ तो उनकी मुचलका राशि जब्त हो जाएगी।

देरी के अलावा वकीलों की फ़ीस आम आदमी की पहुंच से न्याय के दर को दूर कर देती है। दरअसल, यदि यह कहा जाय कि वकीलों के एक छोटे से वर्ग ने सारी न्याय व्यवस्था को अपने ठेंगे पर रखा हुआ है तो कोई अतिश्योक्ति न होगी। पैसे वालों के लिए ये 'सफल' वकील अदालती कार्यवाही को खींचते जाते हैं। जबकि हर न्यायालय परिसर में ज्यादातर वकील हाथ पर हाथ धरे मक्खियां मारते रहते हैं क्योंकि उनके पास काम नहीं होता? क्या इस व्यवस्था को आमूल-चूल बदलना नहीं चाहिए?

गडकरी जैसे झूठे मुकदमों द्वारा अदालती काम बढाने के लिए कौन जिम्मेदार है? झूठे मुकदमे दायर करने वाले और झूठा बचाव खड़ा कर अदालतों का समय बर्बाद करने वाले गडकरियों और उनके वकीलों की फ़ौज पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं होती मुकदमे खत्म होने पर सब अपने-अपने घर चले जाते हैं और नये सिरे से झूठे मुकदमों का सिलसिला शुरू हो जाता है। क्या इसका कोई तोड़ नहीं हो सकता?

देरी के लिए प्रायः अदालतों की कमी का रोना रोया जाता है। सवाल है कि कानूनी न्याय करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जज कहां से लाये जायें? क्यों नहीं कानून के जानकार तमाम वकीलों को, जो कानूनी ज्ञान की एक निश्चित परीक्षा पास करलें, जजों के रूप में काम करने की व्यवस्था की जाती? इस कदम से किसी भी अदालत परिसर में जजों की कमी नहीं रहेगी। फ़िर भी यदि कोई जज 3-4 पेशियों में मुकदमे का निपटारा नहीं कर सकता तो उसे अयोग्य पा कर बर्खास्त करने में क्या हिचक हो सकती है?

न्याय व्यवस्था से देरी और खर्चीलेपन को समाप्त किये बिना जितने मर्जी बेल बांड या मुचलके भरवा लिये जायें, न्याय तो आम आदमी की पकड़ से दूर ही रहेगा। वक्त आ गया है कि देश की सर्वोच्च अदालत भी यह सोचे कि उनकी प्राथमिकता बेल बांड भरवाना है या विवादों का निपटारा करना।

केजरीवाल को यू टर्न तो करना पड़ा है पर इससे न्याय व्यवस्था को जनसुलभ बनाने में बुनियादी परिवर्तनों का मुद्दा आंखों से ओझल नहीं किया जा सकता। भारतीय समाज को न्यायिक सुधारों की लम्बी लड़ाई के लिये भी कमर कस लेनी चाहिये।

(संबंधित खबर पेज आठ पर)

मां मोदी की; पत्नी किसकी!

नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी पक्की होने के बाद अपनी मां हीराबा से दो बार टी वी कैमरों के सामने मुलाकात की। गांधीनगर में भावुकता के इस प्रदर्शन ने मोदी को काफ़ी प्रशंसा भी दिलाई। गुजरात दंगों के संदर्भ में लगभग अमानवीय छवि वाले मोदी के मां के समक्ष मानवीय रूप को देखकर उनकी एक नई तस्वीर गढी जाने लगी है। मां-बेटे की इन मुलाकातों के दौरान भाई, भाभी, भतीजे-भतीजी की उपस्थिति ने और चार चांद लगा दिये।

घोर ताज्जुब तब हुआ जब 26 मई को राष्ट्रपति भवन के विशाल प्रांगण में 5000 मेहमानों की उपस्थिति में मोदी के ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में मां को नहीं बुलाया गया। मां ही नहीं, मोदी के किसी भाई या अन्य रिश्तेदार को भी आमन्त्रित नहीं किया गया। भला ऐसा क्यों? क्या मां की इस 'अनदेखी' के पीछे भी कोई राजनीति है?

दरअसल जब से विरोधियों ने मोदी की चार दशक से भी ज़्यादा पुरानी पत्नी जशोदाबेन को खोज निकाला है, मोदी के लिये एक नाजुक संतुलन बनाना जरूरी हो गया। यदि शपथग्रहण के मौके पर वे अपनी मां व अन्य परिजनों को बुलाते तो तुरन्त मीडिया में सुर्खियां बनती कि जशोदाबेन को क्यों नहीं बुलाया गया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार मौजूदा चुनाव में नामांकन भरते समय मोदी को जशोदाबेन का नाम पत्नी के कॉलम में लिखना पड़ा था। अब यह गले की ऐसी फ़ांस है जो न उगले बनती है न निगलते। आनंदीबेन को गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री बनाने वाले मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री अपने मन्त्रिमंडल में 23 कैबिनेट मन्त्रियों में 6 महिलाओं को स्थान दिया है। इससे वे अपने बहुप्रचारित नारी सशक्तिकरण के एजेंडे को भी रेखांकित करना चाहते हैं पर जशोदाबेन के प्रति जवाबदेही को लेकर उनकी चुप्पी हमेशा एक मर्दवादी प्रश्नचिन्ह की तरह रहने जा रही है।

मन्त्री-पुत्र ने कांग्रेस की छोड़ी यारी, अब सपरिवार भाजपा की तैयारी

फ़रीदाबाद (म.मो.) लोकसभा चुनाव में पूरे देश भर के साथ-साथ हरियाणा व खासकर इस शहर में कांग्रेस की मिट्टी पलीत होने के तुरन्त बाद राज्य के श्रम मन्त्री शिवचरण लाल शर्मा के एक पुत्र नीरज ने कांग्रेस से इस्तीफ़ा देकर उसे इस कदर प्रचारित कराया जैसे कि उन्होंने भारत सरकार के मन्त्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया हो। शहर भर में कौन नहीं जानता कि बाप-बेटों सहित पूरे परिवार की सियासत सदैव आयाराम-गयाराम की ही रही है। इनका सामूहिक उद्देश्य येन-केन-प्रकारेन सत्ता हथियाना ही रहा है। सत्ता चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, बस कोई न कोई सत्ता होनी ही चाहिये। छोटी सत्ता में लूट कमाई का स्तर छोटा रहता है जबकि बड़ी सत्ता में इसका स्तर बड़ा हो जाता है।

अपने नफ़े-नुकसान को तौल कर राजनीति करने में माहिर शिवचरण लाल ने कांग्रेस की इस दुर्दशा का अनुमान तो चुनाव घोषित होने से पहले ही लगा लिया था। इसी के चलते उन्होंने भाजपा नेतृत्व से बातचीत का सिलसिला चला भी रखा था। इससे पहले जब चौटाला (जेल जाने से पूर्व) चढती कला में थे तो उनसे भी इनके सम्बन्ध मधुर थे। एक बार तो ये सम्बन्ध इतने मधुर हो चले थे कि इनके मुकाबले चुनाव लड़ने वाले चौटाला पार्टी के नागेन्द्र भड़ाना को भी खतरा लगने लगा था।

तिकड़मबाज़ी में माहिर व किस्मत के धनी शिवचरण ने एन आई टी से निर्दलीय के रूप में विधानसभा चुनाव 2009 में लड़ा व कांग्रेसी उम्मीदवार एवं मन्त्री ए सी चौधरी को हराकर विजयश्री प्राप्त की थी। उधर 2004 से 2009 तक सत्तासीन रहे कांग्रेसी मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की जनविरोधी नीतियों तथा दिन दूणा रात चौगुणा बढते भ्रष्टाचार ने कांग्रेस की हालत इतनी पतली कर दी कि शिवचरण जैसे 7 निर्दलीय विधायकों की लाटरी लग गयी। हुड्डा को सरकार बनाने के लिये आवश्यक बहुमत जुटाने के लिये इन विधायकों का समर्थन किसी भी कीमत पर चाहिये था। लिहाजा हुड्डा ने सभी निर्दलीय विधायकों की भांति शिवचरण लाल को भी मुंह मांगी कीमत अदा की। कीमत डकारने के बाद पंडित जी ने बयान दिये कि वे तो जन्म-जात कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी रहेंगे।

नये-नये राजस्व मंत्री बने शिवचरण लाल ने जब तहसीलदारों से मंथली सेट करने के लिये उन पर दबाव बनाने के लिये छापेमारी जैसे हथकंडे अपनाने शुरू किये तो मुख्यमंत्री हुड्डा को इन्हें हड़काना पड़ा और औकात में रहने की हिदायत देनी पड़ी। फ़िर भी पंडित जी अपनी हरकतों से बाज नहीं आये तो राजस्व विभाग इनसे छीन लिया और अपेक्षाकृत छोटा, श्रम विभाग दे दिया। यहां भी मन्त्री जी ने न केवल अपने तौर तरीकों को जारी रखा बल्कि लूट की रफ़्तार बढा दी।

हालांकि मुख्यमंत्री हुड्डा की अपनी रफ़्तार भी इस मामले में कोई कम नहीं परन्तु पंडित जी के कारनामों को देखकर उन्हें कुछ ज़्यादा ही सख्ती दिखानी पड़ी; यहां तक कि एक बार तो मन्त्री पद छीनने तक की नौबत आ गयी थी। लेकिन जब-जब मुख्यमंत्री इन्हें घुड़कते थे तब-तब ये भी समर्थन वापसी का इशारा देकर हुड्डा को डराते रहते थे। बस इसी झपटम-झपटा में 5 साल निकल गये। हुड्डा का शोरूम भी चलता रहा और पंडित जी की दुकान भी।

संभवतया अक्तूबर 2014 में होने जा रहे राज्य विधान सभा के चुनावों में कांग्रेस की जो दुर्गति होने वाली है उसका अनुमान किसी भी आम आदमी की अपेक्षा पंडित जी को कहीं अधिक है। ऐसे में जब तक सरकार में उनकी हिस्सेदारी चल रही है, वे उसका पूरा लाभ उठाते रहेंगे। लेकिन चुनाव लड़ने के वक्त तय करेंगे कि किस पार्टी में जाने पर लाभ अधिक प्राप्त होगा।

ख़बर दार

हर्षवर्धन का छिपा वार बेकार
कुर्सी के लिये किरण बेदी बेकरार-

जुगल किशोर गुप्ता

किरण बेदी को दिल्ली में भाजपा का मुख्यमंत्री बनाकर लाने की तैयारी अन्तिम चरणों में है। पार्टी ने यह मान लिया है कि चुनाव हों तो भी और न हों तो भी हर्षवर्धन के मुकाबले किरण बेदी उसे ज़्यादा माफ़िक आयेंगी।

भाजपा नेतृत्व को पता है कि दिल्ली में उनका मुकाबला भ्रष्टाचार के विरुद्ध बिगुल बजाने वाली पार्टी 'आप' से है अन्यथा काफ़ी दिनों से 'आप' के कई विधायक अन्दरखाने भाजपा के हाथों बिक चुके हैं। कोई और समय होता या विपक्ष में कोई और पार्टी होती तो भाजपा ने कब की तोड़ फोड़ कर के अपनी सरकार बनाली होती। अब उनकी नैतिक मजबूरी हो गयी है कि वे किरण बेदी को सामने लायें, जो अन्ना आन्दोलन में केजरीवाल के बराबर खड़ी थी। ऐसे में यदि 'आप' के विधायकों को तोड़ कर समर्थन की नौबत आई तो तर्क दिया जा सकता है कि किरण बेदी के पास इनकी घर वापसी हो रही है। केजरीवाल से बेहद चिढे अन्ना का 'आशीर्वाद' भी किरण बेदी को मिल सकता है।

यदि विधान सभा के लिये पुनःचुनाव कराने पड़े तो भी 'आप' से टूट कर भाजपा में आनेवालों को आसानी रहेगी। यह कहा जा सकता है कि किरण बेदी के मुख्यमंत्री बनने से अन्ना आन्दोलन के संघर्ष की ही सफ़ल परिणति हो रही है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध 'आप' की लड़ाई में जनता को दिग्भ्रमित करने का यह कारगर हथकंडा सिद्ध होगा।

कुछ महिनों से किरण बेदी ने नरेन्द्रमोदी के गुण गाने तेज़ किये हुए थे। जाहिर है, पार्टी में चल रही सोच से उन्हें अवगत रखा गया होगा। हर्षवर्धन, जिन्हें दिल्ली विधान सभा चुनाव में भाजपा ने मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया था, को भी भनक लग ही गयी होगी। अभी लोकसभा चुनाव दूर थे और उसमें भाजपा की अपने दम जीत अनिश्चित थी। ऐसे में जोखिम न लेते हुए हर्षवर्धन ने किरण बेदी पर छिपा वार करने का सहारा लिया।

हर्षवर्धन की ओर से बयान आया कि 'आप' के संयोजक केजरीवाल को अमेरिकी खुफ़िया एजेंसी सी आई ए द्वारा नियन्त्रित मैगसेसे पुरस्कार तथा फ़ोर्ड फ़ाऊंडेशन अनुदान मिला है ताकि वे विदेशी हितों को साध सकें। ऊपर से यह केजरीवाल पर आक्रमण था पर अन्दरखाने चोट की जा रही थी बेदी पर। आखिर बेदी को भी तो मेगासेस पुरस्कार मिला हुआ है और उनका एन जी ओ भी फ़ोर्ड फांउडेशन के अनुदान से ही चल रहा है। दूसरे शब्दों में, अगर केजरीवाल सी आई ए के इशारों पर देशहित के विरुद्ध काम कर रहे हैं तो उसी तर्क से बेदी भी देशद्रोही हुई। लगता है भाजपा नेतृत्व ने हर्षवर्धन के छिपे वार को भांप लिया। तभी लोकसभा चुनाव में बहुमत मिलने पर उन्हें आनन-फानन में मोदी मन्त्रीमंडल में कैबिनेट मन्त्री बना दिया गया। साथ ही बेदी की मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी पर मुहर लगा दी गयी। बस अब तोड़-फ़ोड़ या नये चुनाव का सफ़र तय करना बाकी है। हर्षवर्धन केन्द्र सरकार में मन्त्री बन गये, बेदी दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री बन जायेंगी, पर यह भीतरघात का प्रसंग बताता है कि कुर्सी को लेकर भाजपा में भी वैसी ही उठापटक चलती है जैसी कांग्रेस में।